भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 704

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2026 को दिया जाना है ।

02 श्रावण, 1948 (शक)

सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थिति

704. श्री नीरज डांगी:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में चल रहे सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल कितना बजट आवंटित किया गया है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन आईटी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और उनमें से कितने युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में आईटी प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या पर्याप्त नहीं है, यदि हों, तो सरकार द्वारा इस कमी को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे है; और
(घ) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित युवाओं को आईटी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई विशेष प्रावधान किए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(घ):** सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) भारत में आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है। देश का आईटी क्षेत्र 315 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करता है, जिसमें आईटी सेवाओं का निर्यात लगभग 246 अरब डॉलर है।

भारत में 33,000 से अधिक प्रौद्योगिकी स्टार्टअप भी हैं, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाता है। यह क्षेत्र लगभग 60 लाख पेशेवरों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।

और सभी क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के तेजी से अंगीकरण के साथ, इस विकास को बनाए रखने के लिए डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल विकसित करना महत्वपूर्ण हो गया है।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभाग डिजिटल और आईटी से संबंधित कौशल विकसित करने के लिए कार्यक्रम और पहल लागू कर रहे हैं। ये पहल प्रासंगिक डिजिटल कौशल वाले युवाओं, पेशेवरों, सरकारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों को लक्षित करती हैं।

इसी रणनीति के हिस्से के रूप में, भारत सरकार ने जुलाई, 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम डिजिटल पहुंच, इंटरनेट सामर्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और डिजिटल साक्षरता के विस्तार पर केंद्रित है।

सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य उभरते क्षेत्रों में कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस संबंध में कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

1. **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट):**

- नाइलिट सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी और संचार प्रौद्योगिकी (आईईसीटी) के क्षेत्र में शिक्षा, कौशल और डिजिटल योग्यता कार्यक्रम आयोजित करता है।

इनमें डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम, कौशल आधारित दीर्घकालिक/अल्पकालिक पाठ्यक्रम शामिल हैं।

- देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण देने के लिए देश भर में फैले 56 अपने केंद्र और 9000+ भागीदार संस्थान स्थापित किए गए हैं। इस नेटवर्क के माध्यम से, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कार्यक्रमों के तहत नाइलिट द्वारा 31.92 लाख+ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

इनमें से 4.38 लाख+ उम्मीदवार अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित हैं और 2.23 लाख+ उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों से संबंधित हैं।

- नाइलिट अपने छात्रों के लिए रोजगार के अवसरों को सुकर बनाने के लिए देश भर में अपने केन्द्रों पर रोजगार मेलों का भी आयोजन करता है। पिछले तीन वर्षों में, इन रोजगार मेलों में 33000+ उम्मीदवारों ने भाग लिया है, जिनमें से 12000+ उम्मीदवारों को विभिन्न उद्योगों में शॉर्टलिस्ट/प्लेस किया गया था।

2. **नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी (एनडीयू) प्लेटफॉर्म:**

- एनडीयू प्लेटफॉर्म एआई, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग और अन्य डोमेन जैसे उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ऑनलाइन और मिश्रित कौशल-आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करता है

- इस प्लेटफॉर्म में सेमीकंडक्टर डिजाइन, साइबर सुरक्षा, साइबर फोरेंसिक, उद्योग 4.0 और अन्य उभरते डोमेन में वास्तविक समय के प्रयोग के लिए बिल्ट-इन वर्चुअल लैब भी हैं।

इस मंच के माध्यम से, एक शिक्षार्थी कभी भी-कहीं भी राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) संरेखित पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार डिजिटल विभाजन को पाटने में सहायता करता है।

- अब तक 2.74 लाख+ उम्मीदवारों ने नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म के तहत पंजीकरण कराया है।

3. **फ्यूचरस्किल्स प्राइम कार्यक्रम** एमईआईटीवाई और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) की एक सहयोगी पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को एक अत्याधुनिक डिजिटल प्रतिभा राष्ट्र बनाना है। प्रमुख विशेषताएं हैं:

- एआई, बिग डेटा एनालिटिक्स (बीडीए), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी/वर्चुअल रियलिटी (एआर/वीआर) आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग शामिल हैं।

- वास्तविक रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योग के परामर्श से पाठ्यक्रम विकसित किए जाते हैं।

- इस पोर्टल को कभी भी-कहीं भी उनकी योग्यता और आकांक्षाओं के अनुरूप कौशल प्रमाण पत्र अर्जित करने के लिए एक्सेस किया जा सकता है (https://futureskillsprime.in/)

- अब तक, पोर्टल पर 34 लाख+ उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 23 लाख+ उम्मीदवारों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित/प्रशिक्षित किया गया है।

- फ्यूचरस्किल्स प्राइम पोर्टल को नैसकॉम के टैलेंट कनेक्ट पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है, जो उम्मीदवारों को उद्योग में नौकरी के अवसरों को तलाशने में सक्षम बनाता है।

4. **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)** यह देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 6.39 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के साथ दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल साक्षरता पहलों में से एक है (6 करोड़ के तय लक्ष्य की तुलना में)।

5. **सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए):**

- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना सुरक्षा में मानव संसाधन पैदा करने और जनता के बीच साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए 'सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए)' परियोजना लागू कर रहा है।

- अब तक, देश भर में 6,650 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जिनमें स्कूल/कॉलेजों के छात्रों, शिक्षकों, कानून प्रवर्तन, सरकारी कर्मियों और आम जनता सहित 11.37 लाख+ प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।

- इसके अलावा, हैंडबुक, लघु वीडियो, पोस्टर, ब्रोशर, बच्चों के लिए कार्टून कहानियों आदि के रूप में बहुभाषी जागरूकता सामग्री प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया और www.isea.gov.in और https://staysafeonline.in/ के माध्यम से प्रकाशित और प्रसारित की गई ।

6. **इलेक्ट्रॉनिकी और आईसीटी अकादमी योजना - चरण- II:**

- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में देश भर के संकाय सदस्यों/प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिकी और आईसीटी अकादमी योजना - चरण-II को लागू कर रहा है।

- अब तक, 79,000+ संकाय सदस्यों को 1250+ संकाय विकास कार्यक्रमों (एफडीपी) के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।

7. **कार्य-आधारित शिक्षा (डब्ल्यूबीएल):**

- एमईआईटीवाई, अपने संस्थानों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) स्नातकों/स्नातकोत्तरों को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए "कार्य आधारित शिक्षा (डब्ल्यूबीएल)" कार्यक्रम लागू कर रहा है। डब्ल्यूबीएल परियोजना उम्मीदवारों को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में संस्थानों द्वारा की जा रही विभिन्न डिजाइन/विकासात्मक/अनुसंधान गतिविधियों से अवगत होने का अवसर प्रदान करती है।

- यह कार्यक्रम एमईआईटीवाई संगठनों की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाता है और एससी/एसटी, ईडब्ल्यूएस और महिला उम्मीदवारों की रोजगार क्षमता को बढ़ाता है।

- अब तक, 4213 उम्मीदवारों (एससी -1,268, एसटी -755, ईडब्ल्यूएस -758, और महिला -1,432) को कार्य-आधारित शिक्षा (डब्ल्यूबीएल) कार्यक्रम के तहत कवर किया गया है।

8. **प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक)** इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास (अनुसंधान एवं विकास) संगठन है।

- पिछले तीन वर्षों के दौरान, 10 डोमेन में सी-डैक के स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र कार्यक्रमों के तहत 11,600+ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 5,700+ ने प्लेसमेंट हासिल किया है।

9. **इंडिया एआई मिशन:**

भारत सरकार ने देश में समग्र एआई इकोसिस्टम के विकास के लिए इंडियाएआई मिशन को मंजूरी दी, जो सात स्तंभों के माध्यम से भारत के विकास लक्ष्यों के साथ जुड़ा हुआ है।

- इंडिया एआई मिशन के फ्यूचर स्किल्स स्तंभ के तहत, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और संबंधित उभरती प्रौद्योगिकियों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करके एआई-तत्पर प्रतिभा तैयार करने के लिए इंडियाएआई डेटा और एआई लैब्स की स्थापना की जा रही है।

- इन डेटा और एआई लैब्स का प्राथमिक उद्देश्य क्षमता निर्माण और कौशल विकास है। तदनुसार, प्रयोगशालाएं प्रशिक्षण और प्रमाणन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

- देश भर में 570 इंडियाएआई डेटा और एआई लैब का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें 27 नाइलिट केंद्र और 543 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)/पॉलिटेक्निक शामिल हैं। नाइलिट केंद्रों में स्थापित 27 इंडियाएआई डेटा और एआई लैब चालू हैं।

- अब तक 5500+ उम्मीदवारों ने कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त मूलभूत प्रमाणन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण किया है।

10. **स्किल इंडिया मिशन (सिम):**

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा स्किल इंडिया मिशन (सिम) के तहत विभिन्न कौशल विकास योजनाओं को एकीकृत किया गया है।

- इन योजनाओं - जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (एनएपीएस) और क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम (सीटीएस) - के तहत आईटीआई/नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एनएसटीआई) के ज़रिए आईटी और डिजिटल स्किल की ट्रेनिंग एक अहम हिस्से के तौर पर दी जाती है।

- पिछले तीन वर्षों में, इन योजनाओं के तहत 2.94 लाख+ उम्मीदवारों को सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आईटी-आईटीईएस) डोमेन में प्रशिक्षित किया गया है।

- इसके अलावा, एमएसडीई ने जुलाई 2025 में एसओएआर (एआई तत्परता के लिए कौशलन) पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य भौगोलिक क्षेत्रों में एआई शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्कूली छात्रों (कक्षा 6-12) के बीच एआई जागरूकता और मूलभूत डिजिटल/एआई साक्षरता को शामिल करना है।

चालू वित्त वर्ष में, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

******